Part X: The Scheduled and Tribal Areas

Part X of the Constitution of India deals with the Scheduled and Tribal Areas. It contains provisions regarding the administration and protection of the rights of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other tribal communities in India.

Article 244 deals with the administration of tribal areas in the States, and provides for the appointment of Governors, Chief Commissioners, or Administrators for these areas.

Article 244A deals with the administration of tribal areas in the States and Union Territories, and provides for the appointment of a separate set of administrators for these areas.

Article 244B provides for the constitution of a separate body called the Tribal Advisory Council to advise the Governor or Chief Commissioner on matters affecting the welfare and advancement of the tribal communities in the State or Union Territory.

Article 246A empowers Parliament to make laws for the protection of the rights and interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Article 330 and 332 provide for the reservation of seats for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies, respectively.

Overall, Part X of the Constitution of India lays down the provisions regarding the administration and protection of the rights of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other tribal communities in India, and aims to ensure that these communities are able to enjoy the benefits and protections of the Constitution.

भाग X: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र

भारत के संविधान का भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। इसमें भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य जनजातीय समुदायों के अधिकारों के प्रशासन और संरक्षण के संबंध में प्रावधान शामिल हैं।

अनुच्छेद 244 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, और इन क्षेत्रों के लिए राज्यपालों, मुख्य आयुक्तों या प्रशासकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 244A राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, और इन क्षेत्रों के लिए प्रशासकों के एक अलग समूह की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 244बी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय समुदायों के कल्याण और उन्नति को प्रभावित करने वाले मामलों पर राज्यपाल या मुख्य आयुक्त को सलाह देने के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद नामक एक अलग निकाय के गठन का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 246ए संसद को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं।

कुल मिलाकर, भारत के संविधान का भाग X भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य जनजातीय समुदायों के अधिकारों के प्रशासन और संरक्षण से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करता है, और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये समुदाय लाभों का आनंद लेने में सक्षम हैं और संविधान के संरक्षण।